गृह (GRIHA) ने 10वें गृह सम्मेलन के मौके पर लॉन्च की सिटीज़ रेटिंग

- ग्रीन सिटीज़ बनाने की ओर काउंसिल ने किया प्रयासों को केंद्रित
- ग्लोबल एसोसिएशन फॉर कॉरपोरेट सर्विसेज़ (जीसीएएस) और लोक निर्माण विभाग, महाराष्ट्र सरकार के साथ दो समझौतों पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली, 12 दिसंबर, 2018: स्थायी हरित भविष्य बनाने की विरासत को जारी रखते हुए ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट एसेसमेंट (गृह) काउंसिल ने **श्रीमती हरिंदर सिद्धू**, भारत में ऑस्ट्रेलिया की उच्चायुक्त, **प्रोफेसर इयान जैकब्स**, प्रेसिडेंट एंड वाइस चांसलर, यूनिवर्सटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स (यूएनएसडब्ल्यू), सिडनी, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य हस्तियों की उपस्थिति में **गृह फॉर सिटीज़ रेटिंग** लॉन्च कर 10वें गृह समिट का उद्घाटन किया। गृह फॉर सिटीज़ रेटिंग को किसी शहर के स्थायी विकास के लिए एक ढांचे के तौर पर तैयार किया गया जिसे मौजूदा के साथ ही प्रस्तावित शहरों के ''हरियाली'' मापकर हासिल किया जाएगा। ये रेटिंग ऊर्जा, पानी और कचरा जैसे प्रमुख संसाधनों के प्रदर्शन के लिए मानक तय करता है और स्मार्ट गवर्नेंस, सामाजिक देखभाल और परिवहन जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

उद्घाटन से इतर गृह ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए, एक हरित इमारतों को लेकर प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए **ग्लोबल एसोसिएशन फॉर कॉरपोरेट सर्विसेज़ (जीएसीएस)** और दूसरा महाराष्ट्र की मौजूदा 1608 इमारतों की ग्रीन रेटिंग के लिए **लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), महाराष्ट्र सरकार** के साथ।

अपने स्वागत भाषण में **डॉ. अजय माथुर, महानिदेशक, टेरी ने कहा**, ''भारत और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसे देश हैं जो समान जलवायु साझा करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया समान जलवायु वाला एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास सक्रिय ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम है। इसलिए यह सामूहिक सीख की भरपूर संभावना मुहैया कराता है क्योंकि भारत ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा जहां हमें ढेरों योजनाबद्ध आवास और वातानुकूलित इमारतें देखने को मिलेंगी।''

श्रीमती हरिंदर सिद्धू, भारत में ऑस्ट्रेलिया की उच्चायुक्त ने कहा, ''शहरों को स्थायी बनाना आवश्यक है और इसे संभव बनाने के लिए सरकार एवं समुदाय का साथ आना जरूरी है। सरकार की भूमिका

महत्वपूर्ण है लेकिन इसके लिए निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। यूएनएसडब्ल्यू और गृह काउंसिल जैसे शोध संस्थान स्थायी शहरी भविष्य के लक्ष्य की दिशा में व्यापक योगदान देने के लिए जोड़ने और प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं।''

कार्यक्रम के दौरान गृह काउंसिल ने अपना दृष्टि पत्र भी जारी किया जिसमें कहा गया, ''गृह काउंसिल में हम विश्वसनीयता, ईमानदारी और समावेशन में भरोसा करते हैं और भविष्य के लिए तैयार और स्थायी आवास के लिए भारतीय मूल्यों पर भरोसा करते हैं। गृह ने अपनी बेहतर वेबसाइट भी लॉन्च की जिसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के लिए ज्ञान के भंडार के तौर पर काम आने का है।

प्रोफेसर इयान जैकब्स, प्रेसिडेंट एवं वाइस चांसलर, यूनिवर्सटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स (यूएनएसडब्ल्यू) ने कहा, ''हरित इमारतों और अक्षय ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की सराहना करनी होगी। यूएनएसडब्ल्यू का मानना है कि सरकार और शोध संस्थान स्वाभाविक साझेदार हैं। इसलिए 2018 गृह समिट थीम ''स्थायी आवास के लिए साझेदारियों को बढ़ावा देना'' उन समुदायों पर प्रभाव बढ़ाने के लिए साझेदारियां तलाशने के मुताबिक है जिन्हें हम सेवा मुहैया कराते हैं। मुझे खुशी है कि ऊर्जा, कचरा जल ट्रीटमेंट, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सस्टेनेबल हाउसिंग पर यूएनएसडब्ल्यू, टेरी और गृह के संयुक्त शोध का स्पष्ट उपयोग होगा।''

इस मौके पर **श्री संजय सेठ, सीईओ, गृह काउंसिल** ने कहा, ''10वां गृह समिट उद्योग साझेदारों, डिजाइन प्रैक्टिशनर्स, शिक्षा क्षेत्र के लोगों, नीति निर्माताओं, बहुआयामी और द्विआयामी साझेदारों और अन्य पक्षों के लिए अर्थपूर्ण साझेदारी के माध्यम से स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए सहयोग, चर्चा और नवोन्मेषी एवं स्वदेशी समाधानों पर सामूहिक ज्ञान साझा करने के लिए गतिशील मंच के तौर पर काम करेगा।''

इससे पहले गृह समिट ने स्थायी इमारत नीतियों, उपकरणों और तकनीकों और स्थायी इमारत सामग्रियों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियों, निर्माण प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों पर विभिन्न तकनीकी सत्रों की मेजबानी की। गृह को मात्रात्मक और गुणवत्ता के आधार पर पूरे जीवनचक्र में इमारत के पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के प्रभावी उपकरण के तौर पर जाना जाता है। यह संसाधनों के उपभोग, कचरा पैदा होने और इमारतों और आवासों के संपूर्ण पारितंत्रीय/पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है।

गृह के बारे में

ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट एसेसमेंट (गृह) काउंसिल एक स्वतंत्र, बगैर मुनाफे के काम करने वाली सोसाइटी है जिसे भारत में हरित इमारतों को बढ़ावा देने और प्रशासन करने के लिए द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) और नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। गृह जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए रणनीति के अंतर्गत यूएनएफसीसीसी द्वारा सौंपे गए भारत के नेशनली डिटरमिंड कॉन्ट्रिब्यूशंस (एनडीसी) के अंतर्गत आवासों के माध्यम से उत्सर्जन गहनता में कमी का मूल्यांकन करने के टूल के तौर पर स्वीकार किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

गृह काउंसिल

संतोष रामकुमार 8800697990 | santhosh.ramkumar@grihaindia.org

टेरी:

पल्लवी सिंह: 01124682100 Ext 2422 | pallavi.singh@teri.res.in

एडलमैन:

स्नेह देव 9958000706 | Sneha.Dev@edelman.com